

दि कर्मिक पोस्ट

Email- thekaarmicpost@gmail.com

Global
School Of
Excellence,
Obedullaganj

वर्ष : 11, अंक : 21

(प्रति बुधवार),

इन्दौर, 17 दिसंबर 2025 से 23 दिसंबर 2025

पेज : 8

कीमत : 3 रुपये

वैज्ञानिकों ने स्टैलेग्माइट से जलवायु परिवर्तन और सभ्यता की शुरुआत का लगाया पता



कुर्दिस्तान। मानव इतिहास में उर्वर अर्धचंद्र (फर्टाइल क्रिसेंट) को सभ्यता का पालना कहा जाता है। यह मध्य पूर्व का एक बूमरंग आकार का क्षेत्र है, जहां हजारों साल पहले इंसानों ने पहली बार खेती शुरू की। लेकिन लंबे समय तक वैज्ञानिक इस बात को पूरी तरह नहीं समझ पाए कि उस समय के जलवायु परिवर्तन ने शुरुआती समाजों को कैसे प्रभावित किया। अब कुर्दिस्तान की एक गुफा में मिली एक प्राचीन स्टैलेग्माइट ने इस रहस्य को समझने में नई रोशनी डाली है।

स्टैलेग्माइट एक ऐसा प्राकृतिक स्तंभ होता है जो गुफा की जमीन से धीरे-धीरे ऊपर की ओर बनता है। बारिश का पानी मिट्टी और चूना पत्थर से होकर रिसता है और गुफा में टपकता है। हर बूंद थोड़ा-थोड़ा कैल्साइट जमा करती है, जिससे परतें बनती जाती हैं। इन परतों में उस समय की तापमान, बारिश और पर्यावरण की रासायनिक जानकारी सुरक्षित रहती है। कुर्दिस्तान की गुफा में मिली इस स्टैलेग्माइट का अध्ययन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लगभग 18,000 से 7,500 साल पहले तक लगातार बनती रही। यह समय आखिरी हिमयुग के अंत और आधुनिक गर्म युग (होलोसीन) की शुरुआत का था, वही समय जब इंसानों की जीवनशैली शिकार से खेती की ओर बदल रही थी।

कैसे किया गया अध्ययन?

जालंधर सिंगल यूज प्लास्टिक मामले में सीपीसीबी ने सौंपी रिपोर्ट

पंजाब। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर कड़े कानून होने के बावजूद जालंधर में उनके पालन को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट (संशोधन) नियम, 2021 और पंजाब प्लास्टिक कैरी बैग (नियंत्रण) अधिनियम, 2005 (संशोधित 2016) सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाते हैं। यह बात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने 9 दिसंबर 2025 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में दाखिल अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर कही है।

495 पृष्ठों की यह रिपोर्ट 25 अक्टूबर 2024 को एनजीटी द्वारा दिए आदेश पर दाखिल की गई है। गौरतलब है कि यह रिपोर्ट जालंधर में सिंगल यूज प्लास्टिक से जुड़े नियमों के पालन में कथित चूक

वैज्ञानिकों ने स्टैलेग्माइट की परतों में मौजूद ऑक्सीजन और कार्बन के आइसोटोप, तथा मैग्नीशियम और बैरियम जैसे सूक्ष्म तत्वों का विश्लेषण किया। ऑक्सीजन-18 आइसोटोप बताते हैं कि उस समय कितनी बारिश होती थी। कम मूल्य का मतलब अधिक बारिश से है। कार्बन आइसोटोप पौधों और मिट्टी की स्थिति बताते हैं। अधिक हरियाली का मतलब गर्म और नम जलवायु से है। सूक्ष्म तत्व सूखे की तीव्रता और धूल भरी आंधियों की आवृत्ति के संकेत देते हैं। इन सभी जानकारियों को जोड़कर वैज्ञानिकों ने पूर्वी उर्वर अर्धचंद्र के प्राचीन पर्यावरण की पूरी तस्वीर बनाई। विश्लेषण से पता चला कि इस क्षेत्र के बारिश का पैटर्न विश्वव्यापी तापमान में बदलावों से मेल खाता था, जिसे ग्रीनलैंड की बर्फ में जमी परतों से जाना जाता है। उस समय एक बहुत महत्वपूर्ण ठंडा दौर आया था जिसे यंगर ड्रायस कहा जाता है। ऐसे माहौल में लोगों के लिए स्थायी रूप से बसना मुश्किल था। यही कारण है कि पूर्वी क्षेत्र की आबादी पश्चिमी क्षेत्रों की तुलना में देर से स्थायी किसान समाज में बदली। पूर्व में रहने वाले लोग लंबे समय तक शिकार और भोजन-संग्रह करने वाले घुमंतू जीवन पर निर्भर रहे। हालांकि पर्यावरण कठिन था, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इसी चुनौती ने वहां के लोगों को अधिक लचीला, अनुकूलनीय और संसाधनों को पहचानने में कुशल बनाया। बॉलिंग-आलरॉड नामक गर्म अवधि के दौरान मौसम बहुत बदलता रहता था। इसी बदलाव के कारण लोग छोटी-छोटी जगहों पर उपलब्ध संसाधनों को पहचानने और उन पर निर्भर रहने में माहिर हो गए। शोधकर्ताओं के अनुसार, इन समुदायों ने वर्षों तक बदलते संसाधनों से निपटना सीखा। इसका फायदा उन्हें बाद में तब मिला, जब परिस्थितियां स्थिर हुईं और उन्होंने धीरे-धीरे खेती और स्थायी बसावट की दिशा में कदम बढ़ाया। कुर्दिस्तान की गुफा में मिली स्टैलेग्माइट ने 18,000 से 7,500 साल पुरानी जलवायु का पूरा रिकॉर्ड दिया। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि सभ्यता का जन्म केवल बीज उगाने की कला सीखने भर का परिणाम नहीं था।

जलवायु परिवर्तन, सूखे, तेज हवाएं और अप्रत्याशित मौसम ने इंसानों को अपने परिवेश के साथ लगातार तालमेल बिठाने के लिए मजबूर किया। इसी संघर्ष ने उन्हें और अधिक चतुर, संगठित और नवाचारी बनाया अंततः यही कौशल आगे चलकर गांवों और फिर शहरों के निर्माण की नींव बने।

को लेकर दायर याचिका से जुड़ी है। शिकायत में कहा गया था कि जालंधर में जिम्मेदार अधिकारी सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, बिक्री, वितरण और उपयोग पर लगी कानूनी रोक को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर पाए। यह मुद्दा एनजीटी में 25 अक्टूबर 2024 को उठाया गया था। सीपीसीबी ने रिपोर्ट में बताया कि उसके चंडीगढ़ रीजनल डायरेक्टरेट ने इस मामले में पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी थी। इसके जवाब में पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 28 जनवरी 2025 को अपनी रिपोर्ट साझा की, जिसमें बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाइयों का ब्यौरा दिया गया।

ओमेगा-3 की कमी से जूझ रही दुनिया की 76 फीसदी आबादी

दुनिया की 76 फीसदी आबादी ओमेगा-3 की कमी से जूझ रही है, जो दिल, दिमाग और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया और अन्य संस्थानों के अध्ययन में यह खुलासा हुआ है। विशेषज्ञ इसे वैश्विक स्वास्थ्य संकट मानते हैं और ओमेगा-3 से भरपूर खाद्य पदार्थों और सप्लीमेंट की जरूरत पर जोर देते हैं।

अध्ययन में इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि ओमेगा-3 फैटी एसिड जीवन के हर चरण में सेहत का आधार हैं। यह जहां गर्भावस्था में समय से पहले प्रसव के जोखिम को घटाने में मदद करता है। वहीं शिशुओं में आंखों और दिमाग के विकास में सहायक होता है। साथ ही वयस्कों में दिल की सेहत और रोग-प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। इतना ही नहीं यह अवसाद, याददाश्त कमजोर होना और अल्जाइमर जैसी बीमारियों के खतरे को कम करने से भी जुड़ा है। गर्भ में पलते शिशु से लेकर बुजुर्गों की याददाश्त तक, सेहत की हर कड़ी एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व %ओमेगा-3% से जुड़ी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की तीन-चौथाई आबादी इस अहम पोषक तत्व की कमी से जूझ रही है। यह पोषक तत्व हमारे दिल, दिमाग और सम्पूर्ण स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। यह हैरान कर देने वाली जानकारी यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथैम्पटन और हॉलैंड एंड बैरेट से जुड़े शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किए एक नए वैश्विक अध्ययन में सामने आई है। इस अध्ययन के नतीजे जर्नल न्यूट्रिशन रिसर्च रिव्यू में प्रकाशित हुए हैं। अध्ययन के मुताबिक दुनिया की 76 फीसदी आबादी को स्वस्थ रहने के लिए जरूरी ओमेगा-3 फैटी एसिड, खासकर ईपीए और डीएचए, की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल रही। विशेषज्ञ इसे वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य में एक बड़ी और अनदेखी खाई मान रहे हैं। गौरतलब है कि अपनी तरह का पहला वैश्विक विश्लेषण है, जिसमें सामान्य रूप से स्वस्थ लोगों के लिए जीवन के हर चरण में ओमेगा-3 सेवन को लेकर दी गई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सिफारिशों की समीक्षा की गई है। इसके बाद इनकी तुलना लोगों के वास्तविक आहार से की गई है। इस बारे में अध्ययन और यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया से जुड़ी शोधकर्ता प्रोफेसर ऐनी मैरी मिनिहेन का प्रेस विज्ञप्ति में कहना है, हमने पाया कि जो मात्रा खाने की सलाह दी जाती है और जो हम वास्तव में खा रहे हैं, उनके बीच बड़ा अंतर है। इस अंतर को पाटने के लिए ओमेगा-3 से भरपूर खाद्य पदार्थों और सप्लीमेंट जैसे आसान व किफायती विकल्प जरूरी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह अध्ययन पोषण विशेषज्ञों, डॉक्टरों, खाद्य और सप्लीमेंट उद्योग, नीति-निर्माताओं और आम लोगों को सही जानकारी देने में मदद करेगा। शोधकर्ताओं का कहना है, लॉन्ग चेन पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, खासकर इकोसैपेन्टेनोइक एसिड (ईपीए) और डोकोसाहेक्सैनोइक एसिड (डीएचए) के स्वास्थ्य लाभ इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि साथ ही शोधकर्ताओं का यह भी कहना है कि कई लोगों के लिए ईपीए और डीएचए की सुझाई मात्रा को सिर्फ भोजन से हासिल कर पाना मुश्किल है। ऐसे में उनके लिए आसान और टिकाऊ स्रोत जरूरी हैं। अध्ययन में इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि ओमेगा-3 फैटी एसिड जीवन के हर चरण में सेहत का आधार हैं। यह जहां गर्भावस्था में समय से पहले प्रसव के जोखिम को घटाने में मदद करता है। वहीं शिशुओं में आंखों और दिमाग के विकास में सहायक होता है।



सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को लेकर 17 को करेगा सुनवाई

नई दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह एनसीआर में बिगड़ते वायु प्रदूषण के स्तर से संबंधित याचिका पर 17 दिसंबर को सुनवाई करेगा। सीजेआई सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पामचोली की पीठ ने वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह की दलीलों पर गौर किया, जो न्याय मित्र के रूप में न्यायालय की सहायता कर रही हैं। सिंह ने कहा कि यद्यपि निवारक उपाय मौजूद हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा अधिकारियों द्वारा उपायों का खराब कार्यान्वयन है।

उन्होंने कहा कि जब तक यह अदालत कोई निर्देश नहीं देती, अधिकारी पहले से मौजूद प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं। इस पर सीजेआई ने कहा कि यह मामला बुधवार को तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष आएगा। इस पर सुनवाई होगी। एक अन्य वकील ने बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे से जुड़े आवेदन का हवाला देते हुए कहा कि पहले के आदेशों के बावजूद स्कूल बाहरी खेल गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं। न्याय मित्र ने यह भी कहा कि इस अदालत के आदेश के बावजूद स्कूलों ने इन खेल गतिविधियों को आयोजित करने के तरीके खोज लिए हैं... ये गतिविधियां हो रही हैं।

सीजेआई ने कहा कि हम समस्या को जानते हैं और हम ऐसे आदेश पारित करेंगे जिनका पालन किया जा सके। कुछ निर्देश ऐसे हैं जिन्हें बलपूर्वक लागू किया जा सकता है। इन शहरी महानगरों में लोगों की अपनी जीवनशैली होती है। लेकिन गरीबों का क्या होगा...। न्याय मित्र ने कहा कि गरीब मजदूर सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। इससे पहले पीठ ने कहा था कि वायु प्रदूषण के खिलाफ दायर याचिका को "सामान्य" मामला नहीं माना जा सकता, जिसे केवल सर्दियों के महीनों में ही सूचीबद्ध किया जाए। उसने कहा था कि इस समस्या के अल्पकालिक और दीर्घकालिक समाधान खोजने के लिए महीने में दो बार मामले की सुनवाई की जाएगी। बता दें सोमवार को दिल्ली घनी धुंध की चादर में लिपटी रही, जिससे एक्वआई 498 पर पहुंच गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। वायु गुणवत्ता 38 केंद्रों पर 'गंभीर' थी, जबकि दो केंद्रों पर यह 'बेहद खराब' थी। जहांगीरपुरी में एक्वआई 498 दर्ज की गई, जो सभी 40 केंद्रों में सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला केंद्र रहा।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह से मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की मुलाकात

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह से उनके निवास पर मुलाकात कर पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर ग्वालियर में आयोजित कल्याणकारी कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह ने आमंत्रण स्वीकार किया और आगामी 25 दिसंबर को ग्वालियर आने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी मध्यप्रदेश का गौरव थे।



परमाणु ऊर्जा में निजी भागीदारी से निवेश और जवाबदेही का नया अध्याय

परमाणु ऊर्जा विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी देश के इस क्षेत्र के लिए एक अहम कदम है। यह विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जाना है। जानकारी के मुताबिक यह पहली बार परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के परिचालन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की शुरुआत के साथ जवाबदेही के विषय को हल करने से संबंधित है। विधेयक को सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अथवा शांति का नाम दिया गया है और यह परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 तथा परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व (सीएलएनडी) अधिनियम 2010 में संशोधन कर सकता है। इसके माध्यम से नियामकीय कमियों को दूर किया जाएगा और सक्षम विधिक ढांचा तैयार किया जाएगा ताकि इस क्षेत्र में 49 फीसदी तक निजी, खासकर विदेशी निवेश लाया जा सके। रणनीति यह है कि परमाणु ऊर्जा का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जा सके और कोयले पर बहुत अधिक निर्भर हमारे देश में कम कार्बन वाला विकल्प प्रस्तुत किया जा सके। फिलहाल जो नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक हैं वे इसे टिकाऊ ढंग से हासिल करने में सक्षम नहीं हैं।

विशुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए भारत छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) पर दांव लगा रहा है जो करीब 300 मेगावॉट तक बिजली तैयार करते हैं और जिन्हें पारंपरिक बड़े रिएक्टर की तुलना में लगाना आसान है, सस्ता है और इसे काफी तेज गति से किया जा सकता है। सरकार ने एसएमआर पर शोध और उनके विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है। इस मिशन के तहत वर्ष 2033 तक कम से कम पांच एसएमआर का परिचालन शुरू करने का लक्ष्य तय किया गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हालिया यात्रा के दौरान रूस के साथ व्यापक सहयोग इस रणनीति का एक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि इस क्षेत्र में रूस की उल्लेखनीय विशेषज्ञता है। भारत की परमाणु महत्वाकांक्षाएं स्वाभाविक रूप से व्यापक हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र के लिए एक जीवंत और सक्षम वातावरण बनाने पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक होगा। इसके लिए धनराशि जुटाना भी एक चुनौती हो सकता है। देश का लक्ष्य स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता को मौजूदा 8.8 गीगावॉट से बढ़ाकर वर्ष 2047 तक 100 गीगावॉट तक पहुंचाना है। ऊर्जा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार इसके लिए 214 अरब डॉलर पूंजी की आवश्यकता होगी। इसके लिए किफायती दर पर पूंजी जुटाना आवश्यक है। वित्त मंत्रालय के अधीन



आर्थिक मामलों के विभाग ने पहले परमाणु ऊर्जा को अपनी जलवायु वित्त वर्गीकरण (टैक्सोनॉमी) में शामिल करने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि घरेलू स्तर पर जुटाया गया धन सरकार द्वारा अपेक्षित पैमाने को हासिल करने के लिए पर्याप्त होगा या नहीं। वैश्विक स्तर पर परमाणु वित्त को लेकर काफी दुविधा है, जहां विभिन्न क्षेत्र और यहां तक कि उनके भीतर की संस्थाएं भी इसे ग्रीन टैक्सोनॉमी में शामिल करने के दृष्टिकोण में भिन्नता रखती हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका के कई बड़े वित्तीय कारोबारी परमाणु ऊर्जा को ग्रीन टैक्सोनॉमी से बाहर रखते हैं, जबकि यूरोपीय संघ और चीन इसे शर्तों के साथ अनुमति देते हैं, जैसे अपशिष्ट निपटान और सुरक्षा प्रोटोकॉल आदि। परमाणु उत्तरदायित्व कानून में संशोधन भी महत्वपूर्ण होगा, जो परमाणु दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ताओं के साथ-साथ संचालकों तक विस्तारित करता है। यही एक प्रावधान अमेरिका की वेस्टिंगहाउस और फ्रांस की ईडीएफ जैसी विदेशी रिएक्टरों की सबसे बड़ी कंपनियों द्वारा भारत के परमाणु कार्यक्रम में भागीदारी से परहेज का कारण बताया गया है। यह क्षेत्र बारीकी से देखेगा कि भारत इस मुद्दे को कैसे संबोधित करता है। यद्यपि परमाणु ऊर्जा को सबसे सुरक्षित ऊर्जा स्रोतों में से एक माना जाता है, लेकिन इससे संबंधित हादसे-चाहे चेर्नोबिल हो या फुकुशिमा- पारंपरिक औद्योगिक दुर्घटनाओं की तुलना में कहीं अधिक विनाशकारी दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकते हैं। भारत में भोपाल की यूनियन कार्बाइड आपदा का लंबा प्रभाव जनस्मृति में गहराई से अंकित है। इसलिए जनमानस का प्रबंधन और व्यावहारिक क्षतिपूर्ति तंत्र लागू करना उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना कि तकनीक और वित्त तक पहुंच बनाना।

मध्यप्रदेश उत्सव का रंगारंग समापन

भोपाल नई दिल्ली में चल रहे तीन दिवसीय मध्यप्रदेश उत्सव का रविवार को रंगारंग समापन हुआ। मध्यप्रदेश उत्सव की सांस्कृतिक संध्या में उज्जैन की सुप्रसिद्ध लोक कलाकार सुश्री हीरामणि वर्मा ने मटकी लोक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी। इस नृत्य ने दर्शकों को मालवी अंचल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराया।

ढोलक और हार्मोनियम की मधुर धुनों पर आधारित इस नृत्य में कलाकार ने सिर पर मटकी रखकर पारंपरिक गीतों की लय पर भावपूर्ण नृत्य किया, जो मालवी संस्कृति की सरलता, सौहार्द और उल्लास को दर्शाता है। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में कुल 19 बच्चों ने भाग लिया और अपनी रचनात्मकता और प्रतिभा का सुंदर प्रदर्शन किया। तितली, सिपाही, पेड़, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई, झांसी की रानी, नर्स और ट्रैफिक सिग्नल जैसे विभिन्न रूपों में सजे बच्चों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बच्चों ने अपनी वेशभूषा के माध्यम से सामाजिक सरोकारों और राष्ट्रीय मूल्यों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। भोपाल की सुप्रसिद्ध कलाकार सुश्री क्षमा मालवीय के निर्देशन में एक अद्भुत नृत्य नाटिका की भव्य प्रस्तुति दी गई। इस प्रस्तुति ने दर्शकों को आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं भावनात्मक रूप से गहराई तक प्रभावित किया। नृत्य नाटिका में मां नर्मदा की उद्गम कथा, उनके आध्यात्मिक महत्व तथा देवों, ऋषि-मुनियों एवं भगवान शिव से जुड़े प्रसंगों का सजीव चित्रण किया गया। नर्मदे हर नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे भजन पर आधारित इस प्रस्तुति में शिव शंकर के डमरू की गूंज, ओंकारेश्वर के प्राकट्य एवं ओंकार स्वरूप का मनोहारी वर्णन विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। आवासीय आयुक्त श्रीमती रश्मि अरुण शमी को (मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग को) मोस्ट इन्फॉर्मेटिव श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। यह सम्मान मध्यप्रदेश सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए दिया गया है। इस अवसर पर, मध्यप्रदेश सूचना केंद्र, नई दिल्ली से श्री सौरभ मेहरा ने प्रशस्ति पत्र ग्रहण किया। मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग राज्य सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।



जलवायु संकट- सदी के अंत तक मध्य हिमालय में 84 फीसदी तक बढ़ सकता है बाढ़ का खतरा

नई दिल्ली। नई स्टडी के अनुसार, इस सदी के अंत तक मध्य हिमालय में भीषण बाढ़ का खतरा 84 फीसदी तक बढ़ सकता है। ग्रीनहाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। अध्ययन में सामने आया है कि जिन भीषण बाढ़ों के किसी भी साल में आने की आशंका महज एक फीसदी होती है, उनका आकार 2020 से 2059 के बीच 22 से 26 फीसदी तक बढ़ सकता है।

बाढ़ में यह वृद्धि 1975 से 2014 के बीच इस क्षेत्र में दर्ज बाढ़ों के पैमाने की तुलना पर आधारित है। यदि ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन मध्यम स्तर पर रहता है तो 2060 से 2099 तक यह बढ़ोतरी 43 फीसदी तक पहुंच सकती है। नई स्टडी से पता चला है कि इस सदी के अंत तक मध्य हिमालय में आने वाली भीषण बाढ़ों का आकार 84 फीसदी तक बढ़ सकता है। इसका असर भारत-नेपाल में रहने वाले लोगों पर पड़ सकता है। वैज्ञानिकों ने इसके लिए ग्रीनहाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन को जिम्मेदार माना है। यह चेतावनी ब्रिटेन के डरहम विश्वविद्यालय के भूगोलविदों ने दी है, जिन्होंने नेपाल, चीन में बहने वाली कर्णाली नदी पर भविष्य के बाढ़ जोखिम का विस्तृत मॉडल तैयार किया है। यह नदी आगे चलकर भारत के तराई क्षेत्रों को भी प्रभावित करती है। गौरतलब है कि कर्णाली नदी तिब्बत के मापचाचुंगो ग्लेशियर से निकलती है। नेपाल में कर्णाली कही जाने वाली इस नदी को भारत में घाघरा के नाम से जाना जाता है, जो आगे चलकर गंगा में मिल जाती है। अध्ययन में सामने आया है कि जिन भीषण बाढ़ों के किसी भी साल में आने की आशंका महज एक फीसदी होती है, उनका आकार 2020 से 2059 के बीच 22 से 26 फीसदी तक बढ़ सकता है। बाढ़ में यह संभावित वृद्धि 1975 से 2014 के बीच इस क्षेत्र में दर्ज बाढ़ों के पैमाने की तुलना पर आधारित है। यदि ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन मध्यम स्तर पर रहता है तो 2060 से 2099 तक यह बढ़ोतरी 43 फीसदी तक पहुंच सकती है। चिंता की बात है कि यदि उत्सर्जन तेजी से बढ़ता रहा, तो इस अवधि में भीषण बाढ़ का आकार 84 फीसदी तक बढ़ सकता है। इस अध्ययन के नतीजे अंतरराष्ट्रीय जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित हुए हैं, जो स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि आने वाले दशकों में मध्य हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों की जिंदगी किस तरह प्रभावित हो सकती है। शोधकर्ताओं ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि मध्य हिमालय की नदी घाटियां दुनिया की सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित जगहों में से एक है। उदाहरण के लिए सितंबर 2024 में बाढ़ की ऐसी ही एक घटना ने 236 जिंदगियां निगल ली थी। इतना ही नहीं इसकी वजह से 8,400 लोग अपने घरों से बेघर हो गए। इस बाढ़ से नेपाल के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को एक फीसदी का नुकसान हुआ। अनुमान है कि 2050 तक बाढ़ से होने वाला नुकसान नेपाल के वार्षिक जीडीपी के 2.2 फीसदी तक पहुंच सकता है। ऐसे में शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि इस अध्ययन के नतीजे इस क्षेत्र में स्थानीय बाढ़ प्रबंधन में मदद



कर सकते हैं। बाढ़ सिर्फ घर और सड़कें ही नहीं बहाती, यह खाद्य संकट, साफ पानी की कमी और महामारियों के फैलने का भी कारण बनती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ग्रीनहाउस गैसों का बढ़ता उत्सर्जन नहीं थमा तो ये संकट और गहराता जाएगा। डरहम विश्वविद्यालय के डॉक्टर इवो पिंग का इस बारे में प्रेस विज्ञप्ति में कहना है, मध्य हिमालय का घनी आबादी वाला इलाका पहले ही बाढ़ के प्रति संवेदनशील है। अध्ययन से पता चलता है कि बढ़ते उत्सर्जन के साथ बाढ़ की चरम घटनाएं और ज्यादा ताकतवर होती जाएंगी। उनका अंदेशा है कि सदी के अंत तक बाढ़ की ऐसी घटनाएं हर पांच से दस साल में देखने को मिल सकती हैं। वे कहते हैं कि भले ही आज उत्सर्जन रोक दिया जाए, तो भी बाढ़ का खतरा कई दशकों तक बढ़ता रहेगा। ऐसे में अभी कदम उठाना बेहद जरूरी है। अध्ययन में शोधकर्ताओं ने दुनिया भर के विभिन्न शोध केंद्रों से प्राप्त जलवायु अनुमान को हाइड्रोलॉजिकल सिमुलेशन और सांख्यिकीय विश्लेषण के साथ जोड़ा है। इस विश्लेषण के नतीजे दर्शाते हैं कि बाढ़ के पानी में सबसे बड़ा हिस्सा बारिश में वृद्धि से आएगा, वहीं बर्फ और ग्लेशियर के पिघलने की भूमिका अपेक्षाकृत कम होगी। शोधकर्ताओं के मुताबिक भीषण बाढ़ जैसी चरम घटनाएं कम होती हैं, इसलिए इनके बदलाव की सटीक भविष्यवाणी के लिए कई जलवायु मॉडलों का उपयोग करना जरूरी है, ताकि भविष्य का सही अनुमान मिल सके। इस अध्ययन ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि जलवायु परिवर्तन अब भविष्य का खतरा नहीं, बल्कि मौजूदा समय की हकीकत बन चुका है। यह त्रासदी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ऐसे में यदि मध्य हिमालय के लाखों लोगों के भविष्य को बचाना है तो वैश्विक उत्सर्जन में जल्द से जल्द कटौती ही एकमात्र रास्ता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव इंदौर में शून्य से शिखर सम्मान-2025 में हुए शामिल

इंदौर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि इंदौर का अपना एक रोल है। इंदौर में मेट्रोपोलिटन का नक्शा बनाया गया है, जो भविष्य की योजना को साकार करेगा। आज जो मेट्रोपोलिटन का नक्शा बना है, वह 14 हजार किलोमीटर का है। इंदौर से लेकर रतलाम और रतलाम से लेकर शाजापुर तक सराउंडिंग क्षेत्र में यह मेट्रोपोलिटन का नक्शा इंदौर-भोपाल के साथ क्लिन सिटी के रूप में जुड़ाव करेगा। उन्होंने कहा कि भविष्य की दृष्टि से महानगर की श्रेणी में इंदौर का जो क्षेत्र बनेगा उसी आधार पर भविष्य की इमारतें खड़ी होंगी और निर्माण का अगला पड़ाव तय होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को इंदौर में आयोजित शून्य से शिखर सम्मान-2025 में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मेट्रो ट्रेन को भूमिगत भी चलाया जाएगा। इस कार्य में जो राशि लगेगी सरकार देगी। शहर की खूबसूरती को खत्म नहीं होने देंगे। एलिवेटेड रोड भी बनेगा, एलिवेटेड रोड से जनता को जहाँ सुविधा होगी वहाँ उन्हें रास्ते भी देंगे। उन्होंने कहा कि पाँच साल के अंदर विकास परक बजट डबल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी नए अवसर तलाशने और बेहतर तकनीक से जुड़ने की आवश्यकता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी से लेकर सेमी कंडक्टर तक, आईटी से लेकर हेल्थ तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से वेलनेस और टूरिज्म तक, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की तैयारियां जारी हैं। मध्यप्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने में शासन पीछे नहीं रहेगा। कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, सांसद श्री शंकर लालवानी, महापौर श्री पुष्पमित्र भार्गव, संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े, पुलिस आयुक्त श्री संतोष सिंह, कलेक्टर श्री शिवम वर्मा श्री राजेश चेलावत, श्री किशोर चेलावत उपस्थित रहे। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया गया।